अंक 8 मार्च 2019

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

विषय सूची

- अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन – 2019
- हिन्दी में प्रथम तकनीकी संगोष्ठी
- ई-पीएएमएस राष्ट्रीय कार्यशाला
- परियोजना स्वीकृति
- परियोजना प्रबोधन
- राष्ट्रीय जल पुरस्कार
- समाचार में जल क्षेत्र
- के.ज.आ. की वेबसाइट का शुभारंभ
- स्पेन का दौरा
- भारतीय मानक ब्यूरो कोड के विकास में के.ज.आ. की भूमिका
- भारत-यूरोपीय संघ के संयुक्त तकनीकी कार्य समूह
- जलाशय प्रबोधन
- राज्यों की पहल- मिशन काकातिया
- दीर्घा (गैलरी)
- संदर्भ हेतु वेब लिंक
- प्रशासनिक समाचार
- इतिहास

एस. मसूद हुसैन
अध्यक्ष, के.ज.आ.

संदेश

के. ज. आ. ने ओडिशा सरकार के जल संसाधन विभाग एवं विश्व बैंक के साथ बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के तत्वाधान में 13-14 फरवरी 2019 के दौरान भुवनेश्वर में अन्तर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन-2019 का आयोजन किया. यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा जिसमें 29 देशों के 725 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया. तकनीकी सत्र के अलावा, इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे दिशा निर्देशिका, विभिन्न बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजना एवं संचालन तथा रख-रखाव नियमावली भी जारी किए गए.यह ड्रिप के तहत भारत में आयोजित इस तरह का 5 वाँ सम्मेलन था जो देश में बांध सुरक्षा के पहलुओं से संबंधित जागरूकता पैदा करने एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा भारतीय संदर्भ में उनको अपनाने का मार्ग प्रशस्त करने में सफल रहा है. इसी कड़ी में अगला सम्मेलन वर्ष 2020 में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम (आईसीओएलडी) के संग नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा .

बाँध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना का समग्र कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं समन्वय कार्य के.ज.आ. को सौंपा गया है. ड्रिप की सफलता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने लगभग 700 बांधों के पुनर्वास हेतु रू 10,211 करोड़ के वित्तीय खर्च के साथ ड्रिप के दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रस्ताव बनाया है जिसके लिए विश्व बैंक ने सहायता जारी रखने की सहमति प्रदान कर दी है.

सिंचाई, बहुउद्देशीय एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर जल संसाधन , नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की सलाहकार समिति ने 11 फरवरी 2019 को आयोजित 141 वीं बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं जैसे पोलावरम, लखवर एवं उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के साथ जमरानी के लिए संशोधित लागत अनुमान को स्वीकृति दी है.

महत्वपूर्ण ई-गवर्नेंस पहल में शामिल होते हुए के.ज.आ. ने 25.02.19 को हितधारकों को सूचित/जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान एक वेब-आधारित परियोजना मूल्यांकन प्रबंधन प्रणाली (ई-पीएएमएस) का शुभारंभ किया जिससे कि पारदर्शी , त्वरित एवं उत्तरदायी मूल्यांकन सुनिश्चित की जा सके. राजस्थान सरकार की एक परियोजना के लिए पहले से ही इस प्रणाली के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है. मैं सभी राज्य/केन्द्र सरकारी संगठनों से यह आग्रह करता हूँ कि परिकल्पित लाभों को प्राप्त करने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग करें.

हाल ही में, केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा-समूह 'क' के कुछ अधिकारियों की पदोन्नति उच्च प्रशासनिक ग्रेड एवं वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में हुई है एवं तद्नुसार उनकी तैनाती केन्द्रीय सरकार के विभिन्न संगठनों नामतः के.ज.आ., गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड एवं नवीनतम स्थापित कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण में हुई है. मैं उन सभी को बधाई देता हूँ तथा उनकी नई जिम्मेवारियों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ.

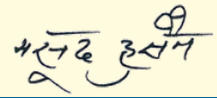

6th INDIA WATER WEEK 2019

Water Cooperation-Coping With 21st Century Challenges

September 24th-28th, 2019, Vigyan Bhawan, New Delhi

अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन - 2019

आईडीएससी-2019 के दौरान श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री, जल संसा.न.वि.एवं गं.सं.मंत्रालय

भुवनेश्वर, ओडिशा में 13.2.19 को आईडीएससी का उद्घाटन समारोह

भुवनेश्वर, ओडिशा में 13.2.19 को आईडीएससी के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रकाशन का विमोचन

श्री एस. मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के.ज.आ., बांध सुरक्षा प्रबंधन में उभरती चुनौतियों पर पूर्ण अधिवेशन सत्र के दौरान

बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के तत्वाधान में 13 से 14 फरवरी, 2019 के दौरान भुवनेश्वर , ओडिशा में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में बांधों के अग्रणी प्राधिकारी व नीति निर्माता, बांध पेशेवरों , वैज्ञानिक एवं शिक्षाविदों सहित 725 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया. इसमें स्पेन, जापान, कनाडा, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, लाओस-पीडीआर, श्रीलंका, इंडोनेशिया इत्यादि जैसे 29 देशों के लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी सम्मलित थे . इस दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान बांध सुरक्षा से संबंधित उत्पादों, प्रौद्योगिकी, उपकरणों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई .

बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति की 39 वीं बैठक

बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति की 39 वीं बैठक का आयोजन 12 फरवरी, 2019 को भुवनेश्वर, ओडिशा में श्री मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. एवं अध्यक्ष, एन सी डी एस की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. के.ज.आ, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रतिभागी एवं सदस्य राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु एवं केरल के एसडीएसओ भी इस बैठक में उपस्थित थे. मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, ओडिशा ने प्रतिभागियों का स्वागत किया. बैठक मे बांधों की स्थिति रिपोर्ट , आपातकालीन कार्य योजना,राष्ट्रीय महत्ता के बांधों , बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल एवं बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया. सदस्यों को लाभान्वित करने हेतु धर्मा पर एक प्रस्तुति भी दी गयी.

डैम हेल्थ एंड रिहैविलीटेशन मानिटरिंग एप्लीकेशन (धर्मा) का प्रदर्शन भी विशेष मीडिया कवरेज के माध्यम से किया गया. धर्मा एसेट प्रबंधन का एक साफ्टवेयर यंत्र (टूल) है जिसका विकास भारत में सभी बड़े बांधों से संबंधित प्रामाणिक डाटा को संकलित करने के लिए किया गया है जोकि बांधों के सुरक्षा पहलुओं की नियमित समीक्षा में सहायक सिद्ध होगा. इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न दिशा निर्देशिकाएं, आपातकालीन कार्य योजना एवं संचालन एवं रख-रखाव नियमावली जारी किए गए.

अगले अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन 2020 में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम (आईसीओएलडी) के साथ नई दिल्ली में किया जाएगा.

के.ज.आ. द्वारा दिशानिर्देशों का प्रकाशन

- बांधों से जुड़े जोखिमों के आकलन और प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश
- जलाशय तलछट के आकलन और प्रबंधन के लिए पुस्तिका
- मैथन बांध, दामोदर घाटी निगम के बांध फील्ड इंजीनियरों के लिए भूकंपीय घटना के बाद निरीक्षण निर्देशिका

संचालन एवं रख-रखाव नियमावलियों का प्रकाशन

- इडमलयार(केरल)
- सरवलार (तमिलनाडु)
- अशोकनाला (ओडीशा)
- मैथन (झारखंड)
- अलमाटी(कर्नाटक)

ईएपी का प्रकाशन

केरल
- कोल्लारकुट्टी
- लोअर पेरियार
- कुंडाला
- मडुपेट्टी
- आर ए हेडवर्क
- पोनमुदी
- अनायीरंकल

तमिलनाडु
- कोडयार

ओडीशा
- हीराकुड बांध

झारखण्ड
- कोनार

कर्नाटक
- भाद्रा
- एच बी हैलो
- हिडकल
- मालप्रभा
- नरायनपुर
- वोतहोल

प्रस्तावित ड्रिप फेज 2 एवं फेज 3

राज्य	18
पुनर्वास के लिए बांध	687
अनुमानित लागत	रु. 10,211 करोड़

हिन्दी में प्रथम तकनीकी संगोष्ठी

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिनांक 7.2.19 को हैदराबाद में हिन्दी में "जल संरक्षण हमारी ज़िम्मेदारी" विषय पर प्रथम तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया.

तकनीकी संगोष्ठी के मुख्य अतिथि श्री एस मसूद हुसैन, माननीय अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग थे. माननीय अध्यक्ष महोदय ने तकनीकी संगोष्ठी का उदघाटन करते हुए अपने अध्यक्षीय संबोधन में जल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं तथा तकनीकी कार्यों को राजभाषा हिन्दी में करने के प्रचार प्रसार की आवश्यकता से प्रतिभागियों को अवगत कराया.

इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन में श्री मोती लाल, संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल आयोग ने कहा कि भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भाषा का अत्यधिक महत्व है.

संगोष्ठी में दो तकनीकी सत्र आयोजित किए गए जिनमें तकनीकी अधिकारियों ने तकनीकी संगोष्ठी के मुख्य विषय से संबंधित उप विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत किए. प्रथम सत्र की अध्यक्षता श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड ने की तथा द्वितीय सत्र की अध्यक्षता श्री एन.के. माथुर, सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग ने की.

संगोष्ठी में निम्नलिखित अधिकारियों ने व्याख्यान प्रस्तुत किए:-

1. श्री जितेंद्र पंवार, निदेशक, बंगलुरु
2. श्री एम रघुराम, अधीक्षण अभियंता, के.ज.आ., हैदराबाद
3. श्री आर. थंगमनी, निदेशक, के.ज.आ., कोयम्बटूर
4. श्री रमेश कुमार एम, निदेशक(अभिकल्प एवं अनुसंधान) के.ज.आ. नई दिल्ली
5. श्री पंकज शर्मा, निदेशक, नदी आंकड़ा निदेशालय-II के.ज.आ. नई दिल्ली
6. श्री डी.एस. चास्कर, निदेशक, के.ज.आ., गांधी नगर
7. श्री आदित्य शर्मा, निदेशक (प्रशिक्षण) के.ज.आ. नई दिल्ली
8. श्री राजेश कुमार, निदेशक (अंतर्राज्यीय मामले -II) के.ज.आ. नई दिल्ली
9. श्री राजीव सिंघल, निदेशक, के.ज.आ., हैदराबाद

श्री मोती लाल, संयुक्त सचिव, के.ज.आ., श्री एन के माथुर, सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), के.ज.आ., श्री एस मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के.ज.आ., श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, श्री आर.के. गुप्ता ,सदस्य सचिव, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण एवं श्री डी. रंगारेड्डी , मुख्य अभियंता , कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन संगठन , के.ज.आ. 7.2.19 को हैदराबाद में हिन्दी में "जल संरक्षण हमारी ज़िम्मेदारी" विषय पर आयोजित प्रथम तकनीकी संगोष्ठी के दौरान स्मारिका का विमोचन करते हुए

10. श्री गोवर्धन प्रसाद, निदेशक, के.ज.आ. नई दिल्ली
11. श्री शशांक भूषण, उप निदेशक, के.ज.आ., नई दिल्ली
12. श्री अजयेन्द्र नाथ त्रिवेदी, प्रबन्धक (राजभाषा) यूको बैंक, कोलकाता

हैदराबाद में आयोजित हिन्दी में प्रथम तकनीकी संगोष्ठी ने अपने आयोजन के तीनों उद्देश्यों अर्थात जल संरक्षण, तकनीकी कार्यों को हिन्दी भाषा में जन-जन तक पहुंचने और हिन्दी के प्रचार प्रसार को सफलतापूर्वक हासिल किया है.

अंत में, धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए श्रीमती रजिन्दर पॉल, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने मुख्य अतिथि एवं मंचासीन सभी वरिष्ठ अधिकारियों का इस संगोष्ठी में पधारने के लिए आभार प्रकट किया.

ई-पीएएमएस राष्ट्रीय कार्यशाला

वृहद् और मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और अंतर-राज्यीय प्रभाव वाले बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करना केंद्रीय जल आयोग के प्रमुख कार्यों में से एक है जिसकी स्वीकृति बाद में जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण की सलाहकार समिति द्वारा की जाती है .

ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन तकनीकी रूप से ठोस एवं विश्वसनीय डीपीआर को अंतिम रूप देने में सहायक होती है जिससे सिंचाई, पेय जल, हाइड्रो पावर एवं बाढ़ सुरक्षा जैसे इच्छित लाभ प्राप्त हो सके.

इससे पहले, जनवरी 2017 में, के.ज.आ. ने राज्य सरकारों , केन्द्र सरकार की एजेन्सियों एवं अन्य हितकारियों के साथ विचार विमर्श पर आधारित ''सिंचाई एवं बहुउदेशीय परियोजनाओं के प्रस्तुतीकरण, मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए दिशा निर्देशिका'' का एक संशोधित संस्करण प्रस्तुत किया था .

ई-गवर्नेंस के संकल्पना के अनुसार, वेब आधारित पीएएमएस प्रणाली के माध्यम से परियोजना प्रस्ताव का आनलाइन प्रस्तुतीकरण करने का प्रावधान इस उपर्युक्त दिशा-निर्देशिका की मुख्य विशेषता है.

राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों /उपयोगकर्ताओं को इससे परिचित कराने के लिए के.ज.आ. द्वारा ई-पीएएमएस पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 25.01.2019 को के.ज.आ. मुख्यालय, नई दिल्ली में किया गया. इस राष्ट्रीय कार्यशाला में राज्य सरकारों, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, के.ज.आ (मु.) के विशेषज्ञ निदेशालयों तथा के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया. इस कार्यशाला के दौरान ई-पीएएमएस का औपचारिक रूप से शुभारम्भ किया गया.

निर्धारित समय का अनुपालन करते हुए, नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-पीएएमएस के माध्यम से आनलाइन प्रस्तुतीकरण, मूल्यांकन एवं दो-तरफा संचार से यह आशा की जाती है कि यह एक लम्बे समयावधि तक तकनीकी सरलता से मूल्यांकन की प्रक्रिया में दक्षता व पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के साथ ही एकरूपता एवं अनुरूपता बनाए रखेगा.

श्री राजीव कुमार, निदेशक, परियोजना मूल्यांकन (केन्द्रीय) निदेशालय, ई-पीएएमएस के नोडल अधिकारी हैं, जो के.ज.आ (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों) में परियोजना प्रस्तावकों, मूल्यांकन एजेन्सियों एवं राज्य सरकार सहित सभी हितधारकों के मध्य समन्वय कार्य करेगें.

श्री अतुल जैन, मु.अ. (आई.बी.ओ.), के.ज.आ., श्री एन.के. माथुर सदस्य (अभि.एवं अनु.), के.ज.आ., श्री एस.के. हलदर, सदस्य (जल आयो.एवं परि.), के.ज.आ., श्री सी.के.एल. दास, मु.अ. (पी.ए.ओ.) , के.ज.आ. एवं डा. किशोर कुमार, उप महानिदेशक, एन.आई.सी., के.ज.आ. (मुख्यालय) नई दिल्ली में 25.2.19 को ई-पी.ए.एम.एस. पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान

परियोजना अनुमोदन

जल संसा, न. वि. एवं गं. सं. मंत्रालय की दिनांक 11/02/2019 को के.ज.आ. (मु.) में आयोजित 141 वीं बैठक में सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का सारांश नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	वर्ग/परियोजना का प्रकार	अनुमानित लागत (करोड) व मूल्य स्तर	परियोजना का लाभ
1	पोलावरम सिंचाई परियोजना का संशोधित लागत अनुमान	आंध्र प्रदेश	वृहद् सिंचाई, राष्ट्रीय परियोजना	रु. 55548.87 (2017-18)	सीसीए 2.91 लाख हेक्टेयर एआइ-4.36 लाख हेक्टेयर उर्जा 960 मेवा.
2	लखवर बहुउद्देशीय परियोजना का संशोधित लागत अनुमान	उत्तराखंड	बहुउद्देशीय, राष्ट्रीय परियोजना	रु. 5747.17 (जुलाई 2018)	सीसीए व एआई 33780 हे. ऊर्जा-300 मेवा.
3	जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संशोधित लागत अनुमान	उत्तराखंड	वृहद् बहुउद्देशीय सिंचाई	रु. 2584.10 (मई, 2018)	सीसीए- 150027 हे. एआई- 295382 हे. ऊर्जा-14 मेवा.
4	बाराबंकी जिले में घाघरा नदी के दांये तट पर बसन्तपुर—खजूरी उपांतीय (मार्जिनल) तटबंध का निर्माण	उत्तर प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	रु. 68.6159 (2018)	लाभांवित क्षेत्र-5184 हेक्टेयर लाभांवित जनसंख्या-15106
5	श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी के बांये तट के खजुहा झुनझुनिया अंधरपुरवा के निर्माण हेतु परियोजना का संशोधित आकलन	उत्तर प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	रु. 46.3726 (2016)	लाभांवित क्षेत्र- 15412 हेक्टेयर लाभांवित जनसंख्या-98350
6	श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी के बांये तट-पर परसा देहरिया तिलकपुर के निर्माण हेतु परियोजना का संशोधित आकलन	उत्तर प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	रु. 37.8629 (2016)	लाभांवित क्षेत्र- 14868.76 हेक्टेयर लाभांवित जनसंख्या-83900

सीसीए - कृष्य कमान क्षेत्र एआई - वार्षिक सिंचाई

परियोजना प्रबोधन

केन्द्रीय जल आयोग, केंद्र द्वारा वितपोषित निष्पादनाधीन जल संसाधन परियोजनाओं की निगरानी करता है. वर्ष 2018-19 के दौरान, के.ज.आ. द्वारा अब तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता वाली चल रही परियोजनाओं के लिए कुल 83 निरीक्षण दौरे किये गए हैं . इन निरीक्षणों के परिणाम के आधार पर, के.ज.आ. के उचित सुझाव के साथ 1664.205 करोड़ रूपए का प्रस्ताव मंत्रालय को भेज दिया गया है.

हाल ही में, नीति आयोग के पदाधिकारी भी इन दौरों में शामिल थे .

बोरोलिया सिंचाई परियोजना (असम)

बरगी डायवर्जन परियोजना, मध्य प्रदेश

दिनांक 05.02.19 - 07.02.19 के दौरान श्री आर.के. पचौरी, मु.अ. (पीपीओ), केजआ., श्री अनन्त कुमार गुप्ता, निदेशक, केजआ., श्री एस.पी. सिंह, उप निदे., केजआ, लखनऊ ओर श्री एम.के. मकवाना, नीति आयोग ने सरयू नहर परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) का दौरा किया

दिनांक 20.02.19 — 22.02.19 के दौरान श्री आर.के. पचौरी, मु.अ., पीपीओ, श्री जी. एल. बसंल, निदेशक, केजआ, श्री एन.के. वेल, उप सलाहकार, नीति आयोग ने गोसी खुर्द परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना), महाराष्ट्र का दौरा किया

राष्ट्रीय जल पुरस्कार

श्री नितिन गडकरी, केन्द्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री एवं श्री यू पी सिंह, सचिव के साथ दिनांक 25.02.2019 को नई दिल्ली में संयुक्त रूप से 14 वर्गों में 82 राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किए.

सभी वर्गों के पुरस्कारों में एक ट्राफी एवं प्रशस्ति पत्र शामिल है. कुछ वर्गों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार विजेताओं के लिए क्रमश: 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए एवं 1 लाख रुपए प्रदान किए गए. राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा भारत में जल संसाधन प्रबंधन के महत्व पर जोर देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था. इस संबंध में प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन हेतु के.ज.आ. ने आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई.

समाचारों में जल क्षेत्र

- मार्च 2020 तक प्रदूषण मुक्त हो जायेगी गंगा : गडकरी (दैनिक जागरण, 01.02.2019).
- सिंधु बेसिन का दौरा करने के लिए भारत को किया आमंत्रित (दैनिक जागरण, 01.02.2019) .
- अगले 81 साल में पिघल जायेगा हिमालय का एक तिहाई हिस्सा (राजस्थान पत्रिका, 06.02.2019)
- सिंचाई के लिए पानी की कमी को दूर कर रहा हाइड्रोजेल (राजस्थान पत्रिका, 12.02.2019)
- नमामि गंगे के 76 प्रोजेक्ट पूरे (पंजाब केसरी, 12.02.2019)
- बनारस से सीधे डिब्रूगढ़ तक जा सकेंगे जलपोत (दैनिक जागरण, 13.02.2019)
- 2024 तक बन जाएगा जमरानी बांध बनने में लगेगें 2584 करोड़ रुपए (फोकस न्यूज, 14.02.2019)
- नमामि गंगे के तहत यमुना के किनारे बसे शहरों के लिए 1387.71 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत (पंजाब केसरी, 19.02.2019) .
- नदी किनारे बसे गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए उपकरण लगेंगे (हिन्दुस्तान, 21.02.2019) .
- चिंताजनक : यमुना का हाल बदतर, मानक से 6400 गुना हुआ प्रदूषण (हिन्दुस्तान, 22.02.2019)
- ललितपुर को राष्ट्रीय जल पुरूस्कार (राजस्थान पत्रिका, 24.02.2019) .
- जल बंटवारा : भारत व पाक के लिए कितना मुफीद विवाद (जनसत्ता, 26.02.2019).
- 'भूजल कोष संचय' पहल को राष्ट्रीय जल पुरुस्कार (राष्ट्रीय सहारा, 27.02.2019)
- पाक से सिंधु जल संधि क्यों है खास (नवभारत टाईम्स, 28.02.2019) .

केन्द्रीय जल आयोग की नवीन वेबसाइट का शुभारंभ

श्री सैयद मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. व अन्य के.ज.आ. पदाधिकारी, दिनांक 19.2.19 को के.ज.आ. (मु.) नई दिल्ली में के.ज.आ. की नवीन वेबसाइट के प्रारम्भ के अवसर पर

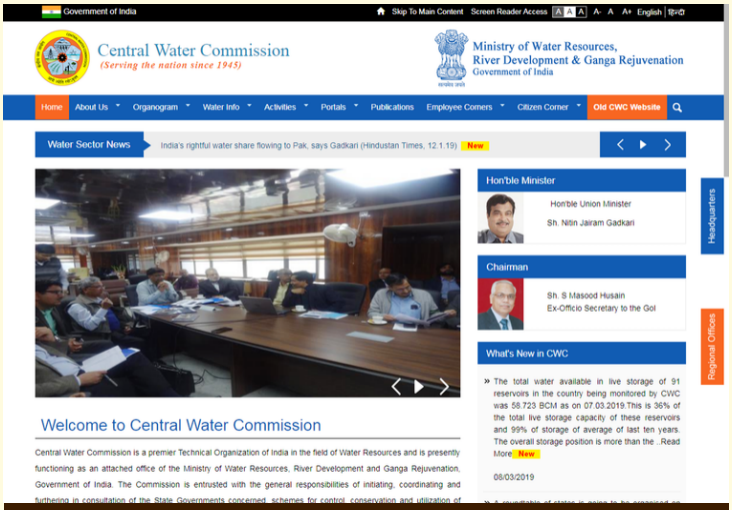

के.ज.आ. की नवीन वेबसाइट का होम पेज

स्पेन में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल

श्री यू. पी. सिंह, सचिव (ज. सं., नदी वि. एवं गं. सं. मंत्रालय) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 17-22 फरवरी, 2019 के दौरान, जल संसाधन डेटाबेस एवं तंत्र, आयोजना एवं प्रबंधन के अनुभवों को साझा करने हेतु स्पेन का दौरा किया. इस प्रतिनिधि मंडल में श्री एस के हलदर, सदस्य (जल आयो. एवं परियोजना), के.ज.आ. एवं श्री राकेश कश्यप, वरि. सं. आयुक्त, एन एच पी, जल सं., नदी वि. एवं गं. सं. मंत्रालय, शामिल थे. इस प्रतिनिधिमडल ने विभिन्न स्थानों/कार्यालयों सहित सेगुरा रिवर बेसिन ऑथोरिटी (मुर्सिया), जुकर रिवर बेसिन ऑथोरिटी (वलेन्सिया), सीईडीईएक्स, सेन्टर फार हाइड्रोलाजी स्टडीज (मैड्रिड), फिजिकल हाइड्रालिक माडलिंग लैब, सेन पेड्रो डेल पिनटर पर अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र ,टूस डैम इत्यादि का दौरा किया एवं स्पेन के अधिकारियों से वार्ता की.

(दायें से बायें) श्री राकेश कश्यप, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, एन.एच.पी., जल संसा.न.वि.एवं गं.सं.मंत्रालय, श्री एस.के. हलदर, सदस्य (जल आयो.एवं परि.), के.ज.आ., श्री यू.पी. सिंह, सचिव, जल संसा.न.वि.एवं गं.सं.मंत्रालय, टूस बांध पर स्पेन के अधिकारियों के साथ

सेगुरा नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष के साथ बातचीत करता हुआ भारतीय प्रतिनिधिमंडल

भारतीय मानक ब्यूरो कोड के विकास में के.ज.आ. की भूमिका

केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन क्षेत्र में एक शीर्ष तकनीकी संस्था होने के नाते, भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस)के जल संसाधन प्रभाग (डब्लू आर डी) और सिविल अभियांत्रिकी प्रभाग(सी ई डी)की गतिविधियों में अपनी भागीदारी के माध्यम से जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन और संबद्ध क्षेत्रों में मानकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. अध्यक्ष, के.ज.आ., वर्तमान में जल संसाधन प्रभाग परिषद के अध्यक्ष हैं. स्वीकृति और मुद्रण हेतु ड्राफ्टकोड एवं भारतीय मानक ब्यूरो कोड में संशोधन का अनुमोदन के.ज.आ. में, अध्यक्ष, के.ज.आ. के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत होता है . हाल ही में, अध्यक्ष द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो कोड के 6 ड्राफ्ट मानकों/संशोधनों को स्वीकृत करने एवं मुद्रण हेतु अनुमोदित किया जा चुका है.

बीआईएस:डब्ल्यूआरडी-16 (681)	भूमिगत पावर हाउस के लिए उपकरणों की माप के प्रकारण स्थान का चुनाव और प्रकार के लिए गाइड
बीआईएस:डब्ल्यूआरडी-16 (691)	नदी घाटी परियोजनाओं में संरचनाओं के लिए मापों के प्रकारों की मार्गदर्शिका और मापन उपकरणों के चुनाव व अवस्थापन की कसौटी -भाग 2 कंक्रीट और चिनाई वाले बांध आईएस 7436 (भाग 2) : 1997
बीआईएस:डब्ल्यूआरडी-01 (11593)	जलमिति - जलमितीय नौकाओं के लिए स्थिति आबद्ध उपस्कर (प्रथम पुनरीक्षण) आईएस 15352/आईएसओ 6420 : 2016
बीआईएस:डब्ल्यूआरडी-01 (11594)	जलमिति– जलमितीय आंकड़ों की संचरण प्रणालियाँ – प्रणालियों की आवश्यकताओं के लिए विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) आई एस 16274/आईएसओ 24155:2016
बीआईएस:डब्ल्यूआरडी-01 (11655)	जलमिति – आयताकार चौड़े-शीर्ष वियर द्वारा खुले चैनल में प्रवाह मापन (प्रथम पुनरीक्षण) आईएस 14974/आईएसओ 3846: 2008
बीआईएस:डब्ल्यूआरडी-08 (659)	मिट्टी तथा पाषाण भरित बाधों , चिनाई बाधों और कंक्रीट बाधों के लिए अभिपूरण अवरोध की डिजाइन के मार्गदर्शी सिद्धान्त (आईएस 11293 का प्रथम पुनरीक्षण , भाग 1 और भाग 2 का सम्मिलन करके)

भारत-यूरोपीय संघ के संयुक्त तकनीकी कार्य समूह का महानदी डेल्टा क्षेत्र का दौरा

श्री मनीष जायसवाल एवं श्री अंकित डुडेजा, उपनिदेशक, एच एस ओ, के.ज.आ. ने 28.01.19 से 02.02.19 के दौरान पर्यावरणीय प्रवाह के आकलन हेतु भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त तकनीकी कार्य समूह-पी आर 2 के सदस्य के रूप में महानदी डेल्टा क्षेत्र का दौरा किया.

डेल्टा के शीर्ष पर कुल 4 नियंत्रण संरचनाओं एवं डेल्टा क्षेत्र में 4 शामिल पर्यावरणीय संवेदी (ईको सेंसेटिव) क्षेत्र/जैव-विविधता हाट स्पाट के का दौरा किया गया . मुण्डाली बैराज, नरज बैराज, जोब्रा बैराज एवं बिरूपा बैराज नियंत्रण संरचनाओं का दौरा किया गया.

इस दौरे में ओडिशा सरकार के वन एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने सहायता एवं सहभागिता किया.

नरज बैराज में अन्य अधिकारियों के साथ संयुक्त तकनीकी कार्य समूह के सदस्य

जलाशय प्रबोधन

के.ज.आ. साप्ताहिक आधार पर देश भर के 91 जलाशयों के वर्तमान भंडारण स्थिति की देखरेख कर रहा है और हर ब्रहस्पतिवार को इसका एक बुलेटिन जारी करता है. इन 91 जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 161.993 घन किमी है जो देश में निर्मित अनुमानित 257.812 घन किमी की सक्रीय भंडारण क्षमता का लगभग 63 % है.

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक-28.02.19 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध वर्तमान भंडारण, 65.536 बी सी एम है जो इन जलाशयों की कुल वर्तमान धारण क्षमता का 40 प्रतिशत है. यह पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान की वर्तमान भण्डारण का 112 प्रतिशत है और पिछले दस वर्षों में औसत भंडारण का 104 प्रतिशत है.

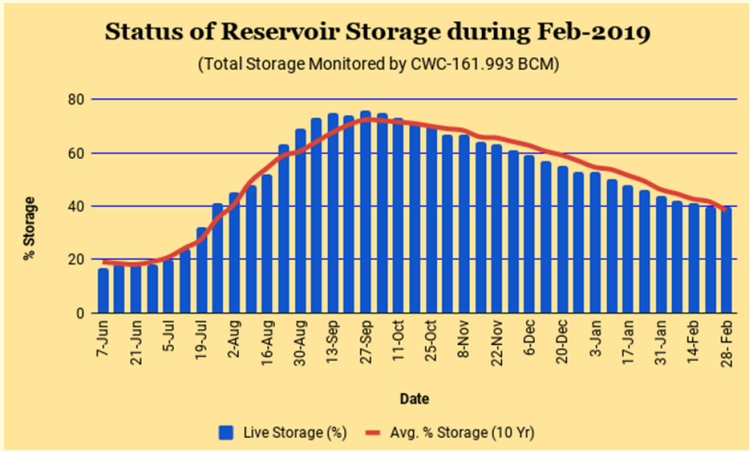

राज्यों की पहल- मिशन काकातिया

राज्य की भूसंरचनात्मक बाध्यताओं के परिणामस्वरूप टैंक, तेलंगाना की जीवन रेखा हैं. तेलंगाना में टैंक निर्माण, सातवाहन के पूर्व काल से ही हो रहा है. काकातीया काल के दौरान, टैको का निर्माण उच्च तकनीकी विशेषज्ञता के साथ होता था. सूखे का मानव जीवन के प्रत्येक स्वरूप पर प्रभाव पड़ता है जबकि ग्रामीण गरीब अधिक गम्भीर रूप से प्रभावित होते हैं.

राज्य की आर्थिक वृद्धि में टैंकों के महत्व को देखते हुए, सिंचाई टैंकों को पुनः शुरू करने हेतु तेलंगाना सरकार ने 'मिशन काकातीया' के नाम से कार्यक्रम प्रारंभ किया है.

मिशन काकातीया का उद्देश्य, सूक्ष्म सिंचाई अवसंरचना के विकास को गति देकर, समुदाय आधारित सिंचाई प्रबंधन को मजबूत करके, टैंकों की पुनरुद्धार के लिए एक वृहद् कार्यक्रम प्रारंभ कर छोटे एवं सीमांत किसानों की कृषि आधारित आय के विकास को बढ़ावा देना है.

राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष 9,306 टैकों को पुनः स्थापित करने की योजना बनाई है (कुल टैंकों का 20 प्रतिशत) जिसमें चरणबद्ध तरीके से 5 वर्षों में सभी 46,531 टैंकों को पुनरुद्धार करने का लक्ष्य शामिल है.

दीर्घा(गैलरी)

आई.आई.टी. रूड़की में दिनांक 01.02.19 को आयोजित जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला में के.ज.आ. के अधिकारियों ने भाग लिया.

कोलकाता में दिनांक 05.02.2019 को सदस्य (नदी प्रबंधन) की अध्यक्षता में दामोदर घाटी जलाशय नियामक समिति की 140 वीं बैठक आयोजित की गई.

कोलकाता में दिनांक 11.02.2019 को आई ई एम पब्लिक स्कूल में टीबीओ.केज.आ. द्वारा स्वच्छता पर कला एवं पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई.

भुवनेश्वर में 12.02.2019 को सुश्री टी.राजेश्वरी, अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने एम एंड ई आर ओ, के.ज.आ. के क्रियाकलापों की समीक्षा की.

कोलकता में 15.02.2019 को गंगा जल के बंटवारे पर भारत-बांगलादेश संयुक्त समिति की 71 वीं बैठक.

मुम्बई में 21.02.2019 को 29 वां वाटर एक्स वर्ल्ड एक्सपो 2019 सम्मेलन, गोरेगांव के उद्घाटन के अवसर पर श्री सैयद मसूद हुसैन, अध्यक्ष के.ज.आ. एवं सुश्री टी.राजेश्वरी, अतिरिक्त सचिव जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय.

सदस्य (अभि. एवं अनु.), के.ज.आ. ने 26.02.2019 को नई दिल्ली में सीस्मिक डिजाइन पैरामीटर्स पर राष्ट्रीय समिति की 34 वीं बैठक की अध्यक्षता की.

सदस्य (अभि. एवं अनु.) के.ज.आ., एव के.ज.आ. के अन्य अधिकारीगण 27.02.2019 को बांध सुरक्षा मुद्दों के संबंध में एन.टी.पी.सी लिमिटेड के पदाधिकारियों के साथ .

पंचेश्वर परियोजना के डी.पी.आर. के संबंध में काठमांडू में 27.02.2019 को भारत व नेपाल के विशेषज्ञों की टीम की तीसरी बैठक में भारतीय टीम का नेतृत्व श्री सैयद मसूद हुसैन ने किया.

सन्दर्भ हेतु वेबसाईटों के लिंक

सिंचाई - सांख्यिकीय वर्ष पुस्तक भारत 2018, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार
http://www.mospi.gov.in/statistical-year-book-india/2018/181

पर्यावरणीय प्रवाह का "जल तनाव" सूचक 6.4.2 मे सम्मिलन, एफएओ-
http://www.unwater.org/app/uploads/2019/01/SDG6_EF_LOW2.pdf

यूएन वाटर एसडीजी 6 सार्वजनिक संवाद रिपोर्ट
http://www.unwater.org/app/uploads/2019/01/WWAP-Full-Report-Design_100119-High-Res.pdf

जल और स्वच्छता पर एसडीजी 6 सिंथेसिस रिपोर्ट-2018, यूएन वाटर
http://www.unwater.org/app/uploads/2018/12/SDG6_SynthesisReport2018_WaterandSanitation_04122018.pdf

खाद्य और कृषि की स्थिति (SOFA): 2018, एफएओ
http://www.fao.org/3/I9549EN/i9549en.pdf

प्रशासनिक समाचार

एच ए जी स्तर पर पदोन्नति

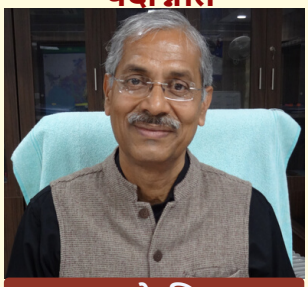

आर के सिन्हा

सदस्य (नदी प्रबंधन), के.ज.आ., नई दिल्ली

डॉ. राकेश कुमार गुप्ता

अध्यक्ष, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद

एस ए जी स्तर पर पदोन्नति

अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान
आदित्य शर्मा	मु.अ., नर्मदा बेसिन संगठन, के.ज.आ., भोपाल
सुशील कुमार	मु.अ., निगरानी (दक्षिण) संगठन, के.ज.आ., बंगलुरू
बी.पी. पांडे	सदस्य सचिव, गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद
नीरज कुमार	सचिव, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, दिल्ली
डी.के. तिवारी	मु.अ., प्रबोधन (मध्य) संगठन, नागपुर
विजय सरन	मु.अ., आई.एम.ओ., के.ज.आ.,(मुख्यालय)
बी.के. करजी	मु.अ., एफ.एम.ओ., के.ज.आ., (मुख्यालय)

एस ए जी स्तर पर स्थानांतरण

अधिकारी का नाम	स्थान से	स्थान पर
शिव नन्दन कुमार	मु.अ., प्रबोधन (मध्य) संगठन, के.ज.आ.नागपुर	मु.अ., सिंधु बेसिन संगठन, के.ज.आ. चण्डीगढ़
अतुल जैन	मु.अ., सिंधु बेसिन संगठन, के.ज.आ., चण्डीगढ़	मु.अ., पी.ए.ओ., के.ज.अ. (मुख्यालय)
नवीन कुमार	मु.अ., आई.एम.ओ., के.ज.आ. (मुख्यालय), नई दिल्ली	सदस्य (जल संसाधन), कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, दिल्ली
सी.के.एल. दास	मु.अ., पी.ए.ओ., के.ज.आ. (मुख्यालय)	सदस्य,गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना

इतिहास — हीराकुण्ड बांध

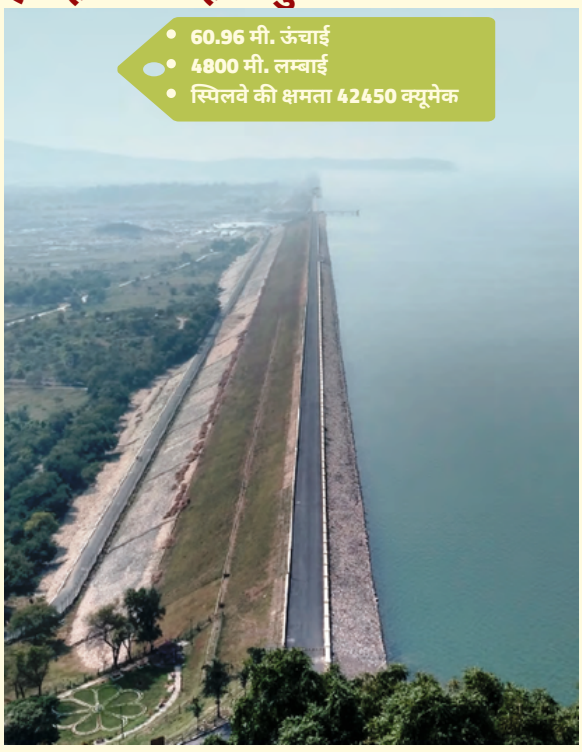

पृष्ठ भूमि	महानदी नदी में बाढ़ के कारण बार-बार तबाही .
1928-1945	ओडिशा बाढ़ जांच समिति, इंजीनियर एम विश्वैश्वरया एवं ओडिशा बाढ़ सलाहकारी समिति द्वारा विभिन्न अध्ययन
	उपरोक्त समस्या पर विचार करने हेतु कटक सम्मेलन (1945) का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता डा बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई . इन्होंने बाढ़, सूखा एवं अकाल की समस्या के लिए नदियों पर बांध बनाने का जोर दिया
1945-1948	श्री ए.एन. खोसला, अध्यक्ष सी.डब्ल्यू.आई.एन.सी. ने बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नेविगेशन एवं विद्युत उत्पादन हेतु नरज, टिकरापारा एवं सम्बलपुर (हीराकुण्ड) में महानदी नदी पर जल संसाधन संरचनाएं बनाने की सिफारिश की थी.
	उड़ीसा प्रांत के राज्यपाल लुईस द्वारा 15 मार्च 1945 को हीराकुंड की आधारशिला रखी गई.
1948	सी.डब्ल्यू.आई.एन.सी. द्वारा हीराकुंड बांध का निर्माण
1957	हीराकुंड बाध का निर्माण कार्य 100.02 करोड़ रू. लागत में पूर्ण किया गया.
ड्रिप के अंतर्गत विकास कार्य	• बांध के बांये तटबंध पर 350 करोड़ की अनुमानित लागत से 5 शिखर गेट (क्रेस्ट गेट्स) के साथ एक अतिरिक्त स्पिलवे का निर्माण किया जायेगा . • डिस्चार्ज क्षमता में 9512 क्यूमेक की अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी.

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री अनुपम प्रसाद, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, (ई.एम.ओ.) - सदस्य
- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता, (पी.एम.ओ.) - सदस्य
- श्री एच.एस. सेंगर, निदेशक, (नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री रवि भूषण कुमार, निदेशक, (टी.सी.) - सदस्य
- श्री एस.डी. शर्मा, निदेशक, (जल प्रणाली अभियांत्रिकी) - सदस्य
- श्री चैतन्य के.एस., उप निदेशक (आई.एस.एम.2) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक (डी एण्ड आर. सम.) - सदस्य
- श्रीमती रजिन्दर पॉल, सहायक निदेशक (राजभाषा) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव

अभिकल्प एवं प्रकाशन
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in